

भारत सरकार  
अंतरिक्ष विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1665

बुधवार, 10 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

अंतरिक्ष में निजी भागीदारी

1665. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार ने वर्ष 2020 में घोषित सुधारों के अनुरूप अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;
- (ख) यदि हाँ, तो विगत चार वर्षों के दौरान की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) कितने उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री

(डॉ. जितेन्द्र सिंह):

\*\*\*\*

(क) एवं (ख)

जी हाँ, वर्ष 2020 में घोषित अंतरिक्ष क्षेत्र सुधारों के अनुसरण में, भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. अंतरिक्ष क्षेत्र में सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए भारतीय अंतरिक्ष नीति, 2023 प्रकाशित की गई।
- ii. सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक उदार और निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति की घोषणा की गई ताकि अंतरराष्ट्रीय निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोगी अनुसंधान के अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके।
- iii. निवेश योजनाएं, जैसे कि i) इन-स्पेस बीज निधि योजना, ii) प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि (टीएएफ) योजना और iii) 1000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि लाई गई हैं।

इसके अलावा, इन-स्पेस, अंतरिक्ष विभाग ने अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाइयां/पहल की हैं:

- i. 'भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दशकीय दृष्टिकोण एवं रणनीति', नामक एक रणनीतिक दस्तावेज अगले दशक में भारत के अंतरिक्ष उद्योग और आर्थिक संभावनाओं को दिशा देने के लिए लाया गया है।
- ii. उद्यमशीलता पूर्व विकास, बीज निधि, प्रौद्योगिकी अंगीकरण निधि और 1000 करोड़ की उद्यम पूंजी निधि जैसी प्रोत्साहन तथा निवेश योजनाएं लागू हैं।
- iii. गैर-सरकारी संस्थाओं (एनजीई) को सहायता प्रदान करने के लिए, इसरो से सुविधा सहयोग और तकनीकी सहायता; इसरो के उपग्रहों के भू-प्रेक्षण (ईओ) डेटा और डेटा उत्पादों तक पहुंच; उपग्रह प्रमोचन सेवाएं, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और डिजाइन प्रयोगशाला उपयोग के लिए मूल्य सहायता नीति लागू की गई है।
- iv. भारतीय उद्योग के लिए इसरो की प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया।
- v. भारतीय एनजीई और सरकार द्वारा 110 अंतरिक्ष गतिविधियों को प्राधिकृत किया गया।
- vi. विभिन्न एनजीई से 600 से अधिक आवेदनों को प्राधिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, परीक्षण सुविधा सहायता, मार्गदर्शन, प्रचार गतिविधियों आदि के लिए सहयोग प्रदान करने हेतु इन-स्पेस के माध्यम से सुविधा प्रदान की गई।
- vii. निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देने और भारतीय तथा विदेशी एनजीई के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतरिक्ष एजेंसियों सहित वैश्विक अंतरिक्ष संगठनों के साथ एनजीई को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है।
- viii. इन-स्पेस ने इसरो और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के सहयोग से "अंतरिक्ष उद्योग के भारतीय मानकों की सूची" तैयार की है। ये मानक एक मज़बूत और व्यापक ढाँचा तैयार करते हैं जो एनजीई द्वारा विकसित की जा रही अंतरिक्ष प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाता है।
- ix. अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित कुल 11 कौशल विकास पाठ्यक्रमों की संकल्पना की गई है। इन गतिविधियों से 700 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।
- x. संचार सेवाओं के विस्तार हेतु अपने उपग्रह लाने के लिए एक एनजीई को कक्षीय स्लॉट आवंटित किया गया है।
- xi. एनजीई की सुविधा और सहयोग के लिए अहमदाबाद स्थित इन-स्पेस मुख्यालय में एक समर्पित तकनीकी केंद्र स्थापित किया गया है।
- xii. इन-स्पेस ने भारतीय अंतरिक्ष स्टार्ट-अप्स यथा, मेसर्स स्काईरूट और मेसर्स अग्रिकुल को नवंबर 2022 और मई 2024 में दो सफल उप-कक्षीय उड़ानों की सुविधा प्रदान की है।

- xiii. छह एनजीई ने कक्षा में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए उन्नीस उपग्रहों को कक्षा में प्रमोचित किया है।
  - xiv. देश भर के शैक्षिक संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र "अंतरिक्ष प्रयोगशाला" की स्थापना।
  - xv. भारत के प्रथम पूर्णतः वाणिज्यिक ईओ उपग्रह समूह के निर्माण हेतु ₹1,200 करोड़ की सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए सहायता संघ की घोषणा की गई और उसका चयन किया गया।
  - xvi. इन-स्पेस ने गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत भर में समर्पित अंतरिक्ष-विनिर्माण समूह स्थापित करने के लिए अन्य राज्य सरकारों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष-श्रेणी घटकों के विनिर्माण के लिए एक मजबूत परितंत्र विकसित करना है।
- (ग) इन-स्पेस ने 110 प्राधिकार-पत्र जारी किए हैं, 95 संयुक्त परियोजना एवं क्रियान्वयन योजना (जेपीआईपी) पर हस्ताक्षर किए, भारतीय उद्योग को विविध इसरो प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण सुसाध्य बनाया और बीज निधि योजना के माध्यम से 7 गैर-सरकारी कंपनियों की सहायता की है। इसके अलावा, एचएएल को एसएसएलवी प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई है और कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से लगभग 700 लोग लाभान्वित हुए।

\*\*\*\*